प्रादेशिक नियोजन एवं भूगोल

भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः दो तथ्यों का विश्लेषण होता है। ये हैं

1. मानव एवं पर्यावरण संबंध, तथा
2. पृथ्वी से संबंधित अवयवों का प्रादेशिक वितरण।

प्रादेशिक वितरण में विषमता पायी जाती है। यह विषमता प्राकृतिक कारकों के साथ-साथ मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। इसी विषमता को दूर करने के लिए प्रादेशिक नियोजन का कार्य किया जाता है। गैलियन (Gallion) महोदय के अनुसार नियोजन का तात्पर्य स्वास्थ्य अर्थात स्वास्थ्य पर्यावरणीय परिस्थिति, सम्पत्ति अर्थात संसाधनों का सही उपयोग और उचित कार्यिक संरचना एवं सुन्दरता अर्थात अपकर्षक निर्मित क्षेत्र एवं जीवनशैली का विकास है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रादेशिक नियोजन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। प्रादेशिक नियोजन का इतिहास 1862 ई० से शुरू होता है, लेकिन सही अर्थों में भौगोलिक तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रादेशिक नियोजन का कार्य बीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ किया गया। 1863 ई० में National Health Commission का गठन ब्रिटेन में और 1914 ई० में गेडिस ने नियोजन पर एक लेख लिखा। नेशनल हेल्थ कमीशन का रिपोर्ट ही प्रादेशिक नियोजन का आधार बना।

National Health Commission

भूगोल अपनी प्रविधि से निम्नांकित रीतियों से नियोजन को योगदान प्रदान करता है:

1. भू-उपयोग सर्वेक्षण, मानचित्रण और विश्लेषण
2. भू-उपयोग परिप्रेक्षण, मानचित्रण और विश्लेषण
3. प्रदेश का परिसीमन

4. जनगणना तथा सांख्यिकीय संकलन के लिए सूचनाओं का प्रादेशिक विवरण
5. सेवाओं का प्रादेशिक वितरण
6. विशेष समस्याएँ

प्रादेशिक नियोजन की प्रथम अनिवार्यता है किसी क्षेत्रीय इकाई का निर्धारण यह कार्य सदैव भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया जाता रहा है। अतः प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत का आधार ही भौगोलिक अवधारणा है। आधिकतर प्रादेशिक नियोजकों के अनुसार प्रदेश निर्धारण के बाद उसके विकास के तीन स्तम्भ होते हैं -

1. जनसंख्या
2. संसाधन, तथा
3. पर्यावरण

और ये तीनों ही स्तम्भ भौगोलिक आधारशिला पर अवस्थित है। अतः भौगोलिक ज्ञान के बिना प्रादेशिक नियोजन का कार्य लगभग असम्भव है।

प्रादेशिक नियोजकों के लिए यह आवश्यक है कि यह वर्तमान जनसंख्या के विविध प्रकार के माँगों के मूल्यांकन करे और पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में दीर्घकालीन शाश्वत विकास नीति का निर्धारण करें।

प्रादेशिक नियोजन के उद्गम

अधिकतर प्रादेशिक नियोजक, प्रादेशिक वैज्ञानिक और भूगोलवेताओं ने प्रादेशिक नियोजन के विकास के उद्गम बताये हैं —

1. नदी बेसिन उद्गम

2. नगर प्रदेश उद्गम

3. आर्थिक-प्रादेशिक उद्गम

4. पदानुक्रमिक प्रादेशिक नियोजन अर्थात बहुस्तरीय नियोजन.

5. विशेष क्षेत्र नियोजन उपागम एवं विकास.

6. समन्वित क्षेत्र विकास उपागम

7. पंचायती राज उपागम

8. शाश्वत नियोजन उपागम.

अतः ऊपर के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत एवं देशों में जहाँ बहुस्तरीय प्रादेशिक नियोजन तकनीकि अपनायी गयी है। लेकिन वर्तमान समय में पंचायती राज नियोजन, टीकाऊ विकास नियोजन और वाटरशेड प्रबंधन जैसे लघुस्तरीय प्रादेशिक नियोजन को अधिक मान्यता दी गई है।